'डूंगरी बांध से सवाई माधोपुर और करौली में 1.25 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी'

'इस बांध का निर्माण संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है'

- मंत्री किरोड़ीलाल, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि ''कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि 76 गांव इससे प्रभावित होंगे। जबकि किसान हितैषी इस परियोजना में सिर्फ 16 गांवों की आबादी ही डूब क्षेत्र में आएगी।''
- मंत्रिमंडल समूह ने कहा कि ''राज्य सरकार, इस परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। उन्हें नियमानुसार मुआवजा प्रदान कर अन्य सुविधाओं के साथ नजदीक ही बसाया जाएगा।''

जयपुर (कासं)। पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले डूंगरी बांध को लेकर शुक्रवार को शासन सचिवालय में मंत्री समूह ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि डूंगरी बांध का निर्माण संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस बांध के निर्माण से मुख्यत: सवाई माधोपुर और करौली की 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी और लोगों को भरपूर पेयजल मिलेगा।

डॉ. मीणा ने कहा कि यह बांध संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के तहत बनाया जाना है। इससे मात्र 16 गांवों की आबादी ही डूब क्षेत्र से प्रभावित होगी जबकि कतिपय लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि 76 गांव प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। उन्हें नियमानुसार मुआवजा प्रदान कर अन्य सुविधाओं के साथ नजदीक ही बसाया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि यह परियोजना व्यापक प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सम्बंध में किसी भी पक्ष से संवाद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण से क्षेत्र में भूमि सिंचित होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों की आय बढ़ने से क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित है। इसी दिशा में यह बांध महत्वपूर्ण कड़ी है।

उन्होंने कहा कि बांध निर्माण से कालीसिंध, पार्वती और चम्बल से समुद्र में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोका जा सकेगा।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि इस परियोजना की सफलता को रोकने के लिए कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से गुमराह न होने की अपील की और राज्य हित में बनाए जा रहे बांध के निर्माण में सहयोग प्रदान करने का आ ान किया।

उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र में आने वाले अधिकतर गांव वर्तमान में मोरेल एवं बनास नदी के बहाव से भी प्रभावित हो रहे हैं।

यह बांध बनास और मोरेल के बहाव क्षेत्र में पानी भरने के हिसाब से बनाया जा रहा है इसलिए इनके बहाव क्षेत्र का ही ज्यादा उपयोग होगा। इससे वर्षा के दौरान आने वाली बाढ़ को रोकने में भी सफलता मिलेगी।

''जना:-उपहार सुपर मार्केट'' का उद्घाटन किया सहकारिता मंत्री ने

यहां ऑर्गेनिक उत्पाद, मसाले और मिलेट्स होंगे उपलब्ध

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को जयपुर के वैशाली नगर में 'जना:-उपहार सुपर मार्केट' का उद्घाटन किया।

- सहकारी समितियों को बनाया जा रहा आर्थिक सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी : मंत्री गौत्तम दक
- प्रदेश में अब तक 201 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 6 गुना ज्यादा है : सहकारिता मंत्री

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियां बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी बनें, इसके लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न नवाचारों और गतिविधियों के माध्यम से सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्त बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर के वैशाली नगर में शुरू किया गया 'जना:-उपहार सुपर मार्केट' एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

दक ने शुक्रवार को जयपुर के वैशाली नगर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) द्वारा ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत शुरू किये गए 'जना:-उपहार सुपर मार्केट' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुपर मार्केट का अवलोकन कर उत्पादों की जानकारी ली। दक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था एनसीसीएफ एवं राज्य स्तर की सहकारी संस्था कॉनफेड के माध्यम से शुरु किये गए इस सुपर मार्केट में विशेष रूप से 'जना:' ब्राण्ड के ऑर्गेनिक उत्पाद एवं 'उपहार' ब्राण्ड के सुप्रसिद्ध मसाले व मिलेट उत्पाद स्टोर पर उपलब्ध करवाये गए हैं। आमजन को एक ही स्थान पर ये गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दर पर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की इस पहल से किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे साथ ही उनके उत्पादों के विक्रय के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' परिकल्पना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक की सहकारी समितियों को वर्तमान समय से अनुरूप नवीन गतिविधियां प्रारम्भ कर आर्थिक समृद्ध बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा तथा राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सहकारी संस्थाओं-समितियों द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जाने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 201 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। यह निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 गुना अधिक है। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) एवं कॉनफेड की प्रबंध निदेशक शिल्पी पांडे एवं एनसीसीएफ की स्टेट हैड मधु शर्मा सहित सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मत्स्य विभाग का ई-ऑक्शन पोर्टल का लोकार्पण

मत्स्य एवं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शुक्रवा रको भारत सरकार की प्रधानमत्री मत्स्य सम्पदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के पैम्फलेट, पोस्टर व बुकलेट का लोकार्पण किया।

जयपुर। मत्स्य एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को विभाग द्वारा एन.ई.एम.एल. के माध्यम से विकसित कराये गये नवीन ई-ऑक्शन पोर्टल एवं लाईसेंस मैनेजमेंट सिस्टम तथा विभाग द्वारा तैयार कराई गई प्रचार सामग्री का लोकार्पण सचिवालय स्थित अपने कक्ष में किया। उन्होंने कहा कि अब मत्स्य विभाग के काम भी ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। श्री बेढम ने कहा कि अब ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से मत्स्य ठेके की बोली लगाने, ठेका राशि जमा कराने, अनुज्ञापत्र जारी करने इत्यादि कार्य विभाग की देख रेख में ऑनलाईन संपादित होगें। शुरूआत में विभाग के ठेके से शेष ''क'' एवं ''ख'' श्रेणी के जलाशयों के ठेके की कार्यवाही ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से की जावेगी। आगामी वर्ष से विभाग के ''ग'' एवं ''घ'' श्रेणी जलाशयों के मत्स्य ठेके की कार्यवाही भी इसी पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किए जाने की योजना है। इस अवसर पर शासन सचिव मत्स्य एवं पशुपालन विभाग डॉ. समित शर्मा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सम्पूर्ण ठेका प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित समयानुसार की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ठेका प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में ठेके से शेष रहे ''क'' एवं ''ख'' श्रेणी जलाशयों का श्रेणीवार एवं जिलेवार विवरण, इनकी आरक्षित दरे एवं निविदा संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। मत्स्य विभाग की निदेशक संचिता बिश्नोई ने बताया कि ठेका प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं का पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बेढम ने विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार की प्रधानमत्री मत्स्य सम्पदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के पैम्फलेट, पोस्टर, बुकलेट इत्यादि का भी लोकार्पण किया। इन सभी प्रचार सामग्री का वितरण राज्य के समस्त विभागीय कार्यालयों को किया जायेगा जिससे आमजन इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभान्वित हो सकेंगे। प्रचार सामग्री में खारे पानी में झींगा पालन, केज कल्चर, आर.ए.एस. एवं बायोफ्लॉक तकनीक की जानकारी एवं मत्स्य पालन से संबंधित सामान्य ज्ञान बुकलेट भी तैयार कराई गई है। लोकार्पण कार्यक्रम में विशिष्ट सचिव, डी.सी. मीणा, विभाग के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ लेखाधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में बेढम ने उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्व मत्स्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विभाग की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना की।

राज्यपाल बागड़े ने ''भारत कला महोत्सव'' में भाग लिया

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हैदराबाद में शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ''भारत कला महोत्सव'' में भाग लिया।

राज्यपाल ने हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में आयोजित इस महोत्सव में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भारत महोत्सव को देश की संस्कृति और कला का अनुपम समारोह बताया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के हथकरघा उत्पादों का अवलोकन करते हुए ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विपणन की दृष्टि से भी इस उत्सव को महत्वपूर्ण बताया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा भी इस दौरान उपस्थित रहे।

नवीन जैन को सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय और नागरिक उड्ययन विभाग की जिम्मेदारी दी

स्वायत्त शासन शासन सचिव रवि जैन को स्थानीय निकाय आयुक्त तथा जे.सी.टी.एस.एल. अध्यक्ष बनाया

- राज्य सरकार ने कोटा व भरतपुर के संभागीय आयुक्त बदले, राजस्व मंडल अजमेर में भी 3 सदस्य बनाए
- वर्ष 2018 बैच के आईएएस डॉ. नीतीश शर्मा को संयुक्त शासन सचिव, सी.एम.ओ. लगाया

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों को तबादला किया। आदेश के मुताबिक नवीन जैन को शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, सम्पदा, स्टेट मोटर गैरेज एवं नागरिक उड्डयन विभाग के पद पर लगाया है। जैन के पास पदेन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एवं महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, राजस्थान जयपुर एवं आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का कार्यभार होगा।

आई.ए.एस. रवि जैन को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान का शासन सचिव तथा स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान के आयुक्त के पद के साथ-साथ जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सिर्विसेज लि. के अध्यक्ष पद पर लगाया है। डॉ. रवि कुमार सुरपुर को शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान एवं शासन सचिव आयोजना, सांख्यिकी विभाग तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. का अध्यक्ष बनाया है। अम्बरीश कुमार को शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात, डॉ. जोगाराम को शासन सविच, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग तथा पंचायतीराज आयुक्त के पद पर लगाया है।

इसी प्रकार रोहित गुप्ता को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर, डॉ. टीना सोनी, को शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, शुचि त्यागी को शासन सचिव परिवहन विभाग तथा देवस्थान विभाग, राजन विशाल को शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के पद पर लगाया है। अर्चना सिंह को शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान, नलिनी काठोतिया को संभागीय आयुक्त भरतपुर, अनिल कुमार अग्रवाल को संभागीय आयुक्त कोटा, हिमांशु गुप्ता को आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचान विभाग तथा राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि. के प्रबंध निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार टीकमचंद बोहरा, केसरमल मीणा और अजीत सिंह राजावत को राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य, निकया गोहाएन को बाल अधिकारिता विभाग में आयुक्त, इकबाल खान को आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, नि:शक्तजन राजस्थान, शुभम चौधरी को आयुक्त, उद्यानिकी राजस्थान जयपुर के पद पर लगाया है।

आई.ए.एस. सुरेश कुमार ओला को आयुक्त, उद्योग, वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, राजस्थान जयपुर तथा आयुक्त (विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय) निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राजस्थान के पद की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। बाबूलाल गोयल को आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर, बचनेश कुमार अग्रवाल को प्रबंध निदेशक राजफैड जयपुर, शाहीन अली खान को अतिरिक्त महानिदेशक, एचसीएम रीपा, मनीष गोयल को संयुक्त शासन सचिव गृह (अपील) विभाग जयपुर, पुरूषोत्तम शर्मा को आयुक्त परिवहन विभाग तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, नवनीत कुमार को आयुक्त, उपनिवेशन विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग बीकानेर के पद पर लगाया गया है।

सुखवीर सैनी को संयुक्त शासन सचिव, गृह (मानवाधिकार) विभाग जयपुर, डॉ. ओमप्रकाश बैरवा को सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग जयपुर, हरफूल सिंह यादव को आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, राजेश वर्मा को सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के पद पर लगाया गया है।

महेन्द्र कुमार खींची को निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर, जुगल किशोर मीणा को अतिरिक्त आयुक्त, (विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय) उद्योग संवर्द्धन ब्यूरो जयपुर, राकेश राजोरिया को आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग जयपुर, ललित कुमार को संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, डॉ. गौरव सैनी को जयपुर नगर निगम आयुक्त के साथ-साथ जयपुर स्मार्ट सिटी लि. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर लगाया है।

डॉ. निधि पटेल को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी राजस्थान जयपुर, डॉ. नीतीश शर्मा को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर, अमिता शर्मा को संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय 2) विभाग जयपुर तथा नरेश गोयल को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर लगाया गया है।

भारतीय वन सेवा के 33 अफसरों का तबादला

- शिखा मेहरा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) जयपुर तथा डॉ. वेंकटेश शर्मा को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि. जयपुर में प्रबंध निदेशक के पद पर लगाया

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर भारतीय वन सेवा के 33 अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

आदेश के मुताबिक शिखा मेहरा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) जयपुर तथा डॉ. वेंकटेश शर्मा को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि. जयपुर में प्रबंध निदेशक के पद पर लगाया है। उदय शंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीईओ कैम्पा जयपुर, राजेश कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना जयपुर, के.सी.ए. अरूण प्रसाद को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर तथा टी.जे.कविथा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर एफसीए जयपुर के पद पर लगाया है।

इसी प्रकार राजीव चतुर्वेदी को राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल जयपुर में सदस्य सचिव, आकांक्षा महाजन को मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के पद पर लगाया है। शैलजा देवल को मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं पदेन राज्य (सिल्वीकल्चरिस्ट) जयपुर, अनूप.के.आर. को मुख्य वन संरक्षक जोधपुर, रूपनारायण मीणा को मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) मुख्यालय जयपुर के पद पर लगाया है।

इसी तरह रामकरण खैरवा को मुख्य वन संरक्षक जयपुर, शारदा प्रताप सिंह को मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, डॉ. टी.मोहन राज को संयुक्त परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जयपुर, अनीता को वन संरक्षण जयपुर विकास प्राधिकरण के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। कपिल चंद्रावल को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव, मोनाली सेन को वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर एवं कार्यकारी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर, हरिकिशन सारस्वत को उपवन संरक्षक, टैरिटोरियल दौसा, आलोकनाथ गुप्ता को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल बूंदी, अजीत उचोई को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल सिरोही, डॉ. रामानंद भाकर को उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद एवं उप वन संरक्षक राजसमंद, मोहित गुप्ता को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल डूंगरपुर, वीरेन्द्र सिंह जोरा को उपवन संरक्षक आयोजना, कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर के पद पर लगाया है। इसी प्रकार, अरूण कुमार डी. को उप वन संरक्षक रामगढ़ विषधारी, टाइगर रिजर्व बूंदी, मानस सिंह को उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, मारिया शाइन ए. को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल भीलवाड़ा, पी.बालामुरूगन को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल अजमेर, कस्तूरी प्रशांत सुले को उप वन संरक्षक टैरिटोरियल पाली, मृदुला सिंह को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चितौडगढ़, बड़े विवेकानंद माणिकराव को सहायक वन संरक्षक बांरा के पद पर लगाया है।

काविया पी.बी. को सहायक वन संरक्षक टैरिटोरियल झुंझुनूं, चेतन कुमार बी.वी. को सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर तथा जी.वेंकटेश को सहायक वन संरक्षक बीकानेर के पद पर लगाया है। राज्य सरकार ने इसी आदेश में डॉ. वेंकटेंश शर्मा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि जयपुर, उदयशंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) जयपुर, राजेश कुमार गुप्ता को परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.डी.पी. एवं सीआईएसईपी जयपुर तथा टी.जे.कविथा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।

एक आईपीएस का भी तबादला

जयपुर । राज्य सरकार ने आदेश जारी कर वर्ष 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर पी.डी. नित्या को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के पद पर लगाया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव ने की प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों पर चर्चा

10 दिसंबर को जयपुर में सीतापुरा स्थित जे.ई.सी.सी. में होगा प्रथम आयोजन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

- देश-विदेश से 4500 से ज्यादा प्रतिभागियों के आगमन की संभावना

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सम्बंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित प्रवासी राजस्थानी दिवस का पहला आयोजन 10 दिसम्बर को जेईसीसी, जयपुर में प्रस्तावित है और यह कार्यक्रम समूचे विश्व में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

बैठक में बताया गया कि इस अवसर पर लगभग 4500 प्रतिभागियों के आने की संभावना है, जिनमें प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति, केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में आरआर-जीआईएस 2024 में प्राप्त एमओयूज़ के आधार पर तैयार 'कॉफी टेबल बुक' का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें लगभग 1500 परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

इसी सत्र में राज्य सरकार की 13 नई नीतियों जैसे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, एनआरआर पॉलिसी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, एआई-एमएल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, ट्री आउटसाइड फारेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, टेक्निकल स्किल पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी तथा एयरो स्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी लॉंच होगी।

मुख्य सचिव ने सभी आठ सेक्टोरल सत्रों की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की। एनआरआर सत्र में वैश्विक प्रवासी समुदाय की भूमिका, निवेश और उद्यिमता के अवसर, विकसित राजस्थान -2047 के लिए प्रवासी युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चाएँ प्रस्तावित हैं।

शिक्षा सत्र में बिट्स पिलानी, आईआईएम उदयपुर, आईआईटी जोधपुर, एमिटी आदि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ नवाचार, कौशल-विकास और गुणवत्ता शिक्षा की दिशा पर चर्चा करेंगे। पर्यटन सत्र में सतत् पर्यटन, डिजिटल सुविधा, होटल निवेश, वैश्विक कनेक्टिविटी और राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के विषयों पर वरिष्ठ उद्योगपतियों और पर्यटन विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य सत्र में भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा अनुसंधान, क्लिनिकल इनोवेशन और प्रवासी चिकित्सकों की भागीदारी पर विभिन्न संस्थानों के वक्ता सुझाव देंगे। उद्योग सत्र में हिंदुस्तान जिंक, वेलस्पन, जेके सीमेंट, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, बोरोसिल, टिटागढ़ रेल, श्री सीमेंट, पिरामल तथा जेसीबी इंडिया सहित देश के प्रमुख उद्योग समूह भाग लेंगे।

जल संसाधन सत्र में स्वच्छ पेयजल, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, शहरी जल संरचना और जल जीवन मिशन से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी।

बैठक में निमंत्रण, पंजीकरण और पुष्टिकरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अब तक कुल 15435 निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, 3260 लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क और फॉलो-अप के लिए 17-सदस्यीय कॉलिंग टीम तैनात की गई है। कुल 5775 बैज तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें गेस्ट ऑफ ऑनर, विशेष आमंत्रित, प्रतिनिधि, मीडिया, सरकारी अधिकारी, सेवा कर्मचारी, आयोजक और प्रोटोकॉल अधिकारियों की अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित हैं।

मुख्य सचिव ने विभागवार तैयारियों की प्रगति पर भी विस्तृत समीक्षा की। उद्योग विभाग की ओर से बताया गया कि जेईसीसी का लेआउट और सेक्टरल सत्रों की संरचना अंतिम रूप में है। स्टेज सेटअप, लॉजिस्टिक्स, कंट्रोल रूम, ब्रांडिंग तथा कैंप ऑफिसेस की तैयारी प्रगति पर है। नगरीय विकास विभाग, जेडीए और जयपुर नगर निगम द्वारा जेईसीसी के आसपास लैंडस्केपिंग, महत्वपूर्ण सड़कों का रख-रखाव, सौंदर्यकरण, प्रमुख भवनों की लाइटिंग, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और आवश्यक साइनज लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

जीएडी द्वारा राज्य अतिथियों के लिए होटल बुकिंग, वाहनों की उपलब्धता, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल डेस्क और सरकारी गैस्ट हाउसों की व्यवस्था पूरी की जा रही है। गृह विभाग और पुलिस द्वारा वीवीआईपी आवागमन, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया गया है। डीआईपीआर द्वारा मुख्य आयोजन हेतु मीडिया योजना, मीडिया रजिस्ट्रेशन, मीडिया सेंटर और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीओआईटी द्वारा स्थल पर हाई-स्पीड इंटरनेट, वीसी समर्थन और तकनीकी अधिकारियों की तैनाती की तैयारी जारी है।

मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों के पंजीकरण को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। सभी विभाग 30 नवम्बर तक 'प्रगति पथ' क्षेत्र और सेक्टोरल सत्रों के लिए अपनी उपलब्धियों पर आधारित संक्षिप्त ऑडियो-विजुअल उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और प्रमुख वक्ताओं की पुष्टि तत्काल उद्योग विभाग को भेजी जाए।

इसके साथ ही सभी विभाग कार्यक्रम से संबंधित सामग्री को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएँ। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस राज्य की गरिमा और अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़ा आयोजन है और सभी विभागों द्वारा उत्कृष्ट समन्वय एवं उच्च स्तर की तैयारियों से इसे सफल बनाया जाएगा।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यटन, गृह, नगरीय विकास, जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, योजना, डीओआईटी, डीआईपीआर, राजस्थान फाउंडेशन तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।